किफायती दाम, बेहतर सुविधा और अच्छा टूर : गौरव झा

आईआरसीटीसी के वेस्ट जोन के ग्रुप जनरल मैनेजर गौरव झा ने डीबीडी को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा कि हम टूरिज्म को और सुविधाजनक बनाते हुए इसे आम लोगों के जेब के हिसाब से पैकेज बनाने जा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने कुल 200 टूर पैकेज लांच किया। इस वर्ष हम 250 पैकेज लांच करेंगे।

▪ डीबीडी संपादक अरुण लाल से चर्चा करते हुए आईआरसीटीसी के वेस्ट जोन के ग्रुप जनरल मैनेजर गौरव झा।

गौरव कहते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देशन में हम आम लोगों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आईआरसीटीसी को 25 वर्ष में भारत सरकार की तरफ से नवरत्न का दर्जा मिलने से हम उत्साहित हैं, और हम यात्रियों की सुविधा में और इजाफा करने में जुटे हुए हैं। हमारे सीएमडी संजय जैन के मार्गदर्शन में कैटरिंग और टिकटिंग के बाद हम टूरिज्म पर पूरा फोकस करने जा रहे हैं। इससे पहले आईआरसीटीसी मिनीरत्न कंपनी थी।

कंपनी शेयर में बहुत अच्छा कर रही है, इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। इसे देखते हुए अब आईआरसीटीसी अन्य नए कार्य करने जा रही है।

150 होटलों और कई विमान कंपनियों से समझौत

वे बताते हैं कि हमने ट्रांस्पोर्ट, एयरलाइंस और होटलों के साथ समझौता कर रखा है। जहां हमें कम मूल्य पर बेहतर सुविधाएं मिलतीं हैं। लगभग 150 होटलों के साथ समझौता किया है। ये हमें पीक सीजन में भी 50 से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सकते हैं। हम रेट और क्वालिटी पर काम करते हैं।

टूरिज्म में अब बढ़ेंगे पैकेज और सुविधाएं

गौरव झा कहते हैं कि हम आम लोगों की सुवधाओं का ध्यान रखते हुए नए नए टूर पैकेज बना रहे हैं। प्राइवेट टूर कंपनियों की अपेक्षा हम ज्यादा भरोसेमंद हैं। हमने यह तय किया है कि किफायती दाम पर बेहतर सुविधा। हम प्राइवेट से कम मूल्य पर बेहतर क्वालिटी देते हैं। एक बार हमारा पैकेज लेने के बाद यात्री को अपनी जेब में हाथ नहीं डालना है। हम उसके रहने, खाने और यात्रा की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

हर टूर के साथ होता है टूर मैनेजर

गौरव बताते हैं कि हम हर टूर में एक टूर मैनेजर भेजते हैं, जो यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखता है। यदि किसी को टूर के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो टूर मैनेजर उसे तत्काल हल करता है। यदि टूर मैनेजर को समस्या हल करने में कोई दिक्कत होती है, तो आईआरसीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी उस समस्या का तत्काल निवारण करते हैं। कहने का अर्थ है कि यात्री के पास 24 घंटे आईआरसीटीसी का सपोर्ट होता है।

लास्ट मोमेंट में कैंसलेशन पर कम चार्ज लिया जाएगा

गौरव बताते हैं कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे हर यात्री को एक बेहतर सुविधा मिले। इसके तहत हम यह भी ध्यान रखते हैं कि यदि लास्ट मोमेंट में किसी को किसी तरह की एमरजेंसी के कारण टूर कैंसल करना होता है तो हम कम से कम पैसे काट कर उन्हें उनके पैसे वापस कर सकें।

भारत गौरव ट्रेन

भारत गौरव ट्रेन एक मॉडल ट्रेन है। इसमें स्लीपर (नॉन-एसी), एसी थ्री, एसी टू टायर के कोच हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के लोकप्रिय पैकेज तैयार करते हैं। 600-700 सीटों की इस ट्रेन में इन्फोटेनमेंट सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ट्रेन में ताज़ा भोजन तैयार करने के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित पेंट्री कार है। यह ट्रेन हर महीने में दो पैकेज करती है। भारत गौरव ट्रेन और अन्य टूरिस्ट ट्रेन पैकेज की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी वैस्ट जोन ने केंद्रीयकृत मोबाइल और ह्वाट्सएप नं 8287931886 जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आईआरसीटीसी की वेबसाइट https://www.irctctourism.com देखें।

न्यूज़ ब्रीफ

गुजरात विधानसभा में इमरान खेड़ावाला ने की सुरक्षा की मांग

गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में इकलौते मुस्लिम विधायक इमरान खेड़ावाला ने मंगलवार को सदन में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कुछ विधायकों ने उन्हें एक विशेष समुदाय का व्यक्ति बताया। साथ ही उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणियां भी की। विधायक खेड़ावाला ने इस मामले में स्पीकर शंकर चौधरी से सुरक्षा की मांगी।

केरल में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन का रास्ता साफ

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा ने मंगलवार को निजी विश्वविद्यालय विधेयक को पारित कर दिया गया, जिससे राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन का रास्ता साफ हो गया। समिती द्वारा जांच किए गए इस विधेयक को विधानसभा में तीखी बहस के बाद पारित किया गया। मामले में राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने इस विधेयक का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह केरल के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक प्रगतिशील कदम है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे।

शशि थरूर ने उठाया अवैध रूप से मछली पकड़ने का मुद्दा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को लोकसभा में केरल में अवैध रूप से मछली पकड़ने का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने सरकार से तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के जरिये मछली पकड़ने की प्रतिबंधित विधि बुल ट्रॉलिंग और कृत्रिम रोशनी या लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान थरूर ने कहा कि भारत सरकार ने हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय जल में मछली पकड़ने के लिए बुल ट्रॉलिंग और कृत्रिम रोशनी या एलईडी लाइट का उपयोग करके मछली पकड़ने के तरीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन केरल में यह सब हो रहा है।

केरल में इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी का शव मिला

पथानामथिट्टा। केरल में पेट्टा रेलवे स्टेशन के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक 24 वर्षीय महिला अधिकारी का शव मिला। महिला अधिकारी की पहचान पथानामथिट्टा के कूडल निवासी मेघा के रूप में हुई है, जो पेट्टा के पास पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह एक संदिग्ध आत्महत्या का मामला है। दूसरी तरफ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक की हत्या के मामले में तमिलनाडु के डीजीपी और तिरुनेलवेली जिले के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने चार सप्ताह के अंदर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

जगदीप धनखड़ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से नकदी बरामदगी पर चर्चा के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे समेत सभी दलों के नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मंगलवार को सदन के सदस्यों की ओर यह मुद्दा उठाया गया था।

दिल्ली के बजट में शिक्षा-स्वास्थ्य और सड़क से पानी तक खोला खजाना

सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 100000 करोड़ का बजट

एजेंसी । नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च (मंगलवार) को दिल्ली की नई सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों सहित आम लोगों के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। एक तरह उन्होंने दिल्ली की पुरानी आप सरकार पर आम लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ नई योजनाओं का ऐलान किया, जिससे दिल्ली के लोगों की जिंदगी पहले के मुकाबले आसान हो जाएगी। गुप्ता का यह बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 31.5 फीसदी बड़ा है।

- स्वच्छता और पानी के लिए 9000 करोड़ आवंटित
- दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये महीने की राशि दी जाएगी, 5100 करोड़ का आवंटन

सरकार 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को शुरू हुआ था। आज रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट का फोकस दिल्ली के आम लोगों पर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी। इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया। इससे आम लोगों को सस्ते दाम पर भोजन मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं। सरकार ऐसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली पर सरकार का फोकस

- मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क और पानी का खास ध्यान रखा गया है। सरकार दिल्ली के लोगों के पानी के संकट को दूर करने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आनेजाने में आसानी होगी।

दिल्ली वासियों को मिलेगा साफ पानी

- गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर घर साफ पानी पहुंचाने पर होगी। इसके लिए सरकार पूरे सीवर सिस्टम को अपग्रेड करेगी। जल आपूर्ति और स्वच्छता पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके लिए सरकार ने बजट में 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल नई वाटर पाइपलाइन बिछाने के लिए करेगी। सीवर लाइनों का विस्तार करेगी। इससे दिल्ली के हर व्यक्ति को साफ पानी मिलेगा।

महिलाओं की सुरक्षा पर बढ़ेगा फोकस

- सरकार ने महिलाओं पर बजट में फोकस किया है। इसके लिए सरकार का जोर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर होगा। इसके लिए दिल्ली में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सड़क और पुल सहित इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 28,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। महिला समृद्धि योजना के लिए उन्होंने 5,100 करोड़ रुपये आवंटितक करने का एलान किया।

सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब्स खुलेंगी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोली जाएंगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से प्रयोगशाला खोली जाएगी। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर अलग-अलग भाषाओं के बारे में सिखाया जाएगा। सरकार स्मार्ट क्लासेज के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

यमुना की सफाई के लिए 9000 करोड़ खर्च होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना की सफाई पर सरकार फोकस बढ़ाया जाएगा। इस पर 9000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही 500 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने का काम होगा। अभी सभी ट्रीमेंट प्लांट पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। सरकार ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाएगी ताकि गंदा पानी यमुना में नहीं जा पाए।

महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये

सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये के आवंटन किया है। इस पैसे से दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भाजपा ने चुनावों के दौरान इस योजना का ऐलान किया था। इस पैसे से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

विधायक फंड के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन

- उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में अब विधायक निधि की बड़ी भूमिका होगी। इसके लिए सरकार विधायक निधि के वास्ते 350 करोड़ रुपये का आवंटन कर रही है। इससे सभी विधायकों को अपने इलाकों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध होगा। नई सरकार में विधायकों को विकास कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं होगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 6874 करोड़ आवंटन

- रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर होगा। इसके लिए 6874 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। सरकार ने राजधानी के 10 से 12 अस्पतालों को 1,000 करोड़ का आवंटन किया है। इस पैसे से इन अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

बुलडोजर कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार को 'सुप्रीम' फटकार

- याचिकाकर्ताओं को घर बनाने की अनुमति

एजेंसी । नई दिल्ली

प्रयागराज में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और याचिकाकर्ताओं को अपने घर दोबारा बनाने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओक और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

याचिकाकर्ताओं को मिली राहत, लेकिन शर्तों के साथ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने खर्च पर घर दोबारा बना सकते हैं। हालांकि, उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी। यदि अपील खारिज हो जाती है, तो उन्हें अपने खर्च पर ही घरों को ध्वस्त

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मानकर घरों को ढहा दिया था। अतीक अहमद की 2023 में हत्या हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के दावे को खारिज कर दिया।

24 घंटे में ढहाए गए घर, कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनका कहना था कि शनिवार रात को नोटिस दिया गया और अगले दिन घर तोड़ दिए गए, जिससे उन्हें अपील करने का मौका ही नहीं मिला। एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि 8 दिसंबर 2020 को पहला नोटिस दिया गया था, फिर जनवरी और मार्च 2021 में भी नोटिस भेजे गए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुचित ठहराते हुए सरकार के दावे को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश की अनदेखी

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में जारी अपने दिशानिर्देशों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि बिना पूर्व नोटिस किसी घर को नहीं गिराया जा सकता। घर के निवासियों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देना होगा। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए। ध्वस्त करने का आदेश अंतिम रूप दिए जाने के बाद 15 दिन तक रोक लगानी होगी ताकि प्रभावित लोग अपील कर सकें या वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें।

लोकसभा में फाइनेंस बिल पास

TMC और कांग्रेस ने किया हंगामा

एजेंसी । नई दिल्ली

बजट सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में फाइनेंस बिल 35 संशोधनों के साथ पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के तहत यह बिल पेश किया है। बिल पर 24 मार्च से बहस चल रही थी।

TMC सांसदों का प्रदर्शन, शिवराज पर हमला

फाइनेंस बिल पास होने से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। वे केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को मनरेगा फंड न देने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए उन्हें ₹अमीरों का दलाल₹ कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज बंगालियों और गरीबों के खिलाफ हैं और मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए काम न करने के कारण ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया।

संसद में हंगामे के बावजूद फाइनेंस बिल पास

हालांकि, TMC और कांग्रेस के विरोध के बावजूद फाइनेंस बिल को बहुमत से पास कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद में टकराव और बढ़ने की संभावना है।

कांग्रेस ने किरेन रिजिजू के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

उधर, कांग्रेस ने लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया।

'जम्मू-कश्मीर के हिस्से से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान'

एजेंसी । संयुक्त राष्ट्र

भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने मंगलवार को पाक पर करारा हमला करते हुए जम्मू-कश्मीर में अवैध कब्जा वाले हिस्से को खाली करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने यह चेतावनी दी। उन्होंने ये टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अनुकूलता को बढ़ावा देने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की खुली बहस में कीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के संदर्भ में बोलते हुए हरीश ने कड़े शब्दों में कहा, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जो उसे खाली करना होगा। हरीश का यह जवाब यूएनएससी की खुली बहस के दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद आया है।

- संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाक को जमकर लगाई लताड़

अनुचित टिप्पणी पर चेताया

भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि भारत यह देखने के लिए बाध्य है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, इस तरह के बार-बार संदर्भ न तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं।

मंच का ध्यान न भटकाए

इस दौरान हरीश ने कहा कि हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वह अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अधिक विस्तृत उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने से परहेज करेगा।

पहले भी फटकार लगाई थी भारत ने

पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के झूठे आरोप लगाए थे। भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में कड़ी फटकार लगाई थी और उसके आरोपों को खारिज कर दिया था। इससे पहले लंदन में 5 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान के पास पीओके को खाली करने के साथ ही कश्मीर मुद्दे का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा।

'छावा' देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी

केंद्रीय मंत्रियों संग संसद में होगी फिल्म की स्क्रीनिंग

एजेंसी । नई दिल्ली

विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'छावा' को लेकर एक और विवाद गर्माया है, दूसरी ओर फिल्म को दर्शकों से इतना प्यार मिला है कि ये इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने 500 करोड़ का जादूई आंकड़ा पार कर लिया है। इसी बीच अब छावा की संसद में स्पेशल स्क्रीनिंग होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 27 मार्च को संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी और पीएम मोदी व अन्य केंद्रीय मंत्री साथ में विक्की कौशल की ये फिल्म देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य मंत्री इस स्क्रिनिंग में मौजूद होंगे। खबर है कि फिल्म में संभाजी महाराज का किरदार निभाने वाले एक्टर विक्की कौशल समेत फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू के लोग भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद होंगे।

बता दें इससे पहले पीएम मोदी ने 'छावा' की तारीफ की थी। मराठी साहित्य सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने कहा था- इन दिनों 'छावा' की धूम मची हुई है।